भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4349
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 5 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है

देश में इलेक्ट्रिकल वाहन

4349. श्री टी के रंगराजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने इलेक्ट्रिकल वाहन प्रचालन में हैं; और

(ख) इलेक्ट्रिकल वाहनों के संबंध में सरकार का नीतिगत दृष्टिकोण क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढावा देने और इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 (चरण-I) से दो वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एक योजना नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ा दिया गया और अंतिम विस्तार दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक है। इस योजना के चार घटक हैं, अर्थात मांग सृजन, प्रौद्यगिकी मंच/अनुसंधान एवं विकास, चार्जिंग अवसंरचना और प्रायोगिक परियोजना।

मांग सृजन के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत इसके व्यापक अंगीकरण को सुगम बनाने के लिए अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के खरीददारों को मांग प्रोत्साहन उपलब्ध है। इस समय यह स्कीम चूंकि कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। यह विभाग देश में चलने वाले कुल इलेक्ट्रिक वाहनों के केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, दिनांक 03.04.2018 तक सरकार ने इस स्कीम के तहत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 1,95,317 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को सहायता दी है।

इसके अलावा, इस नई प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता/संवर्धन को समर्थ बनाने के लिए योजना के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के तहत विशिष्ट परियोजनाओं का वित्तपोषण भी किया गया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकासित करना था।

इस योजना की अधिसूचना में यह प्रावधान है कि स्टेकहोल्डरों से इनपुट और भविष्य में निधियों के पर्याप्त आवंटन के साथ चरण-I के बाद कार्यान्वयन हेतु चरण-I में प्राप्त अनुभव और उपलब्धि के आधार पर स्कीम की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।

तदनुसार, सरकार ने शून्य उत्सर्जन वाहनों और सहायक प्रौद्योगिकियों को आरंभ करने के लिए ट्रांसफॉरमेटिव मोबिलिटी को बढ़ाने हेतु एक कार्यनीति विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की है।

****